मेन्स मास्टर

भारत के कर्ज के बोझ पर विवाद

संदर्भ

यह लेख मुख्य रूप से भारत की आर्थिक स्थिति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा की गई हालिया टिप्पणियों पर चर्चा करता है, जो दो मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है: भारत के ऋणों की स्थिरता के बारे में चिंताएं और भारत की विनिमय दर व्यवस्था का पुनर्वर्गीकरण। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में 2028 तक भारत के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 100% तक पहुंचने, जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता और भारत जैसे विकासशील देशों पर वैश्विक ऋण रुझानों के प्रभाव के बारे में आईएमएफ के अनुमानों पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, इसमें ऋण प्रबंधन में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों, आर्थिक विकास के बावजूद स्थिर क्रेडिट रेटिंग, चालू वित्तीय चिंताओं और अल्पकालिक चुनौतियों और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के बीच आवश्यक संतुलन को शामिल किया गया है।

आईएमएफ टिप्पणियाँ:

• ऋण स्थिरता संबंधी चिंताएँ:

• आईएमएफ का अनुमान है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत का सामान्य सरकारी ऋण वित्तीय वर्ष 2028 तक सकल घरेलू उत्पाद का 100% तक पहुंच सकता है।

• जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लचीलापन बढ़ाने के लिए वित्तपोषण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

• विनिमय दर व्यवस्था का पुनर्वर्गीकरण:

• केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से प्रभावित रुपये के संकीर्ण बैंड के कारण भारत की विनिमय दर व्यवस्था को "फ्लोटिंग" के बजाय "स्थिर व्यवस्था" के रूप में लेबल किया गया।

ऋण और वैश्विक रुझान का प्रभाव:

• ऋण की दोहरी भूमिका:

• विकास में सरकारी उधार की भूमिका को स्वीकार करता है, लेकिन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सीमित वित्तपोषण, बढ़ी हुई लागत और सुस्त विकास के कारण अत्यधिक ऋण प्रगति में बाधा डालता है।

• वैश्विक ऋण रुझान:

• 2022 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण बढ़कर 92 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जिसमें विकासशील देशों का हिस्सा लगभग 30% था, जिसका श्रेय महामारी, जीवन-यापन संकट और जलवायु परिवर्तन को दिया गया।

• ऋण असमानता:

• विकासशील देशों को विकसित देशों की तुलना में अधिक उधारी लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधन आवंटित करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।

भारत की चुनौतियाँ और रेटिंग:

• ऋण प्रबंधन और क्रेडिट रेटिंग:

• तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत स्थिर क्रेडिट रेटिंग से जूझ रहा है, जिसका कारण कमजोर राजकोषीय प्रदर्शन, उच्च ऋण और कम प्रति व्यक्ति आय है।

• ऋण-से-जीडीपी अनुपात और राजकोषीय जिम्मेदारी:

• भारत का ऋण-से-जीडीपी अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पार कर गया, आंशिक रूप से महामारी संबंधी व्यवधानों के कारण।

वर्तमान राजकोषीय चिंताएँ:

• राजकोषीय फिसलन और व्यय:

• मजबूत कर संग्रह के बावजूद, सब्सिडी और रोजगार गारंटी योजनाओं पर बढ़ते खर्च के कारण वित्त वर्ष 2014 में राजकोषीय फिसलन की संभावना बनी हुई है।

• सब्सिडी खर्च और चुनाव:

• बढ़ी हुई सब्सिडी रोजगार वृद्धि और ग्रामीण आजीविका के बारे में सवाल उठाती है, खासकर आसन्न चुनावों के साथ।

तात्कालिक चुनौतियाँ और दीर्घकालिक दृष्टिकोण:

• आईएमएफ अनुमान बनाम अल्पकालिक चिंताएं:

• जबकि आईएमएफ के अनुमान मध्यम अवधि की चुनौतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं, तत्काल ध्यान सबसे खराब स्थिति से बचने के लिए, विशेष रूप से चुनावी वर्ष में, राजकोषीय सुधार पथ का पालन करने पर रहता है।

• कूटनीतिक प्रबंधन:

• भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऋण और राजकोषीय नीतियों का प्रबंधन करते हुए अल्पकालिक चुनौतियों का समाधान करना।

उल्फा के साथ शांति समझौते को समझना

उल्फा का गठन:

• **पृष्ठभूमि**: उल्फा की उत्पत्ति बांग्लादेश के "अवैध आप्रवासियों" के खिलाफ असम आंदोलन (1979-1985) से हुई, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1979 को हुई थी, जिसका उद्देश्य अरबिंद राजखोवा, अनुप चेतिया और परेश बरुआ द्वारा सशस्त्र साधनों के माध्यम से एक संप्रभु असम की स्थापना करना था।

शांति प्रक्रिया की समयरेखा:

• प्रारंभिक वर्ष: एक दशक की भर्ती और प्रशिक्षण के बाद, उल्फा ने अपहरण और हत्याएं शुरू कर दीं, ऑपरेशन बजरंग (1990) के दौरान सरकारी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा और असम को एक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया।

• **सल्फा गठन और बाहरी समर्थन:** उल्फा सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद, एक समूह ने आत्मसमर्पण कर दिया (सल्फा) जो बातचीत में शामिल था, कथित तौर पर लक्षित हत्याओं के लिए इस्तेमाल किया गया था। उल्फा को विदेशी आतंकवादी समूहों और खुफिया एजेंसियों से समर्थन प्राप्त हुआ।

• **उतार-चढ़ाव वाले शांति प्रयास:** 2003 और 2009 में सैन्य हमलों के कारण उल्फा को बांग्लादेश और भूटान से निष्कासन का सामना करना पड़ा। शांति समूह बनाने और युद्धविराम के बावजूद, संगठन ने शत्रुता फिर से शुरू कर दी।

उल्फा-केंद्र-असम सरकार शांति समझौता:

• **समझौते के मुख्य बिंदु:** शांति समझौते में उल्फा को हिंसा छोड़ना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना, असम के विकास में ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश करना, राजनीतिक मांगों को संबोधित करना और नागरिकता अधिनियम के कुछ वर्गों से छूट की मांग करना शामिल है।

आगे की चुनौतियां:

• **शेष उग्रवाद:** हालांकि मुख्यमंत्री उग्रवाद में कमी का दावा करते हैं, म्यांमार के सागांग डिवीजन में बरुआ के उल्फा (आई) समूह के लगभग 200 लड़ाके बने हुए हैं।

• **बरुआ का विरोध:** बरुआ असम की संप्रभुता को संबोधित किए बिना चर्चा का विरोध करते हैं, जबकि सरकार अलगाव की कोई इच्छा नहीं होने का दावा करती है, जिससे बातचीत जटिल हो जाती है।

• **बातचीत की कोशिशें:** मतभेदों के बावजूद बरुआ को शांति वार्ता के लिए मनाने की लगातार कोशिशें जारी हैं.

ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल उन्नयन क्यों आवश्यक है?

संदर्भ

यह लेख शहरीकरण के बीच भारत में ग्रामीण युवाओं की जरूरतों को संबोधित करने के महत्व पर केंद्रित है। यह ग्रामीण युवाओं को बनाए रखने, शहरी क्षेत्रों में प्रवास को रोकने और उन्हें अपने गांवों में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसमें प्राथमिक आय स्रोत के रूप में खेती के प्रभुत्व, वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा परिदृश्य में चुनौतियों और ग्रामीण शिक्षा और कौशल विकास के उत्थान के उद्देश्य से चल रही पहलों पर चर्चा की गई है।

ग्रामीण आय का मुख्य स्रोत:

• **खेती का प्रभुत्व:** कृषि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिक आय स्रोत बनी हुई है, बच्चे अक्सर कृषि कार्य के माध्यम से परिवार की आय में योगदान करते हैं।

• **व्यवसायों में बदलाव:** हालाँकि, किसानों द्वारा गैर-कृषि नौकरियों के लिए कृषि छोड़ने की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, जिससे कृषि संकट पैदा हो रहा है और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता का संकेत मिल रहा है।

प्रवासन पर नियंत्रण:

• **व्यावसायिक प्रशिक्षण:** ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने से रोकने के लिए, ग्रामीण परिवेश में ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का आह्वान किया गया है।

• **स्थानीय कौशल विकास:** 'स्किल्स ऑन व्हील' जैसी पहल को ग्रामीण छात्रों को उनके गांव के आसपास उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए दोहराए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा परिदृश्य:

• **आईटीआई और प्लेसमेंट चुनौतियाँ:** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) मौजूद हैं, लेकिन ग्रामीण आबादी के लिए पर्याप्त प्लेसमेंट अवसरों की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण शिक्षा में कौशल विकास पर सीमित ध्यान दिया जाता है।

• **युवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण:** ग्रामीण युवाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिससे ग्रामीण परिवेश में आगे बढ़ने की उनकी क्षमता में बाधा आ रही है।

ग्रामीण शिक्षा में सुधार:

• **कौशल-युक्त शिक्षा:** ग्रामीण शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के भीतर ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी और जीवन कौशल को एकीकृत करना चाहिए।

• **अन्य देशों से सीखना:** मेक्सिको और भूटान जैसे देशों के उदाहरण दूरदराज के क्षेत्रों में टेली-स्कूलों और मूल्य-आधारित पाठ्यक्रम के लाभों को दर्शाते हैं, जिससे दृष्टिकोण और आकांक्षाओं में सुधार होता है।

पहल और अवसर:

• **संगठनात्मक प्रयास:** एनआईआईटी फाउंडेशन और प्रथम इंस्टीट्यूट जैसे संगठन ग्रामीण बच्चों के लिए कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान कर रहे हैं।

• **हाइब्रिड कौशल कार्यक्रम:** यूनिसेफ और स्व-शिक्षण प्लेटफार्मों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम उद्योग-विशिष्ट और जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण और डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों को पूरा करते हैं।

प्रीलिम्स बूस्टर

चंद्रमा से लेकर यूरोपा तक, 2024 में छह अंतरिक्ष मिशनों के लिए उत्साहित होंगे

🛰️ यूरोपा क्लिपर (नासा):
- बृहस्पति के चंद्रमा, यूरोपा का पता लगाने का मिशन, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे संभावित रूप से एक विशाल खारे पानी का महासागर स्थित है।
- इसका उद्देश्य अलौकिक जीवन के आवास के रूप में यूरोपा की क्षमता की जांच करना है।
- स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च विंडो 10 अक्टूबर, 2024 को खुलती है।

🟡 आर्टेमिस II लॉन्च (नासा):
- नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा, जिसका लक्ष्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना है, जिसमें पहली महिला और रंगीन व्यक्ति शामिल हैं।
- चंद्रमा की कक्षा में जाने के लिए एक चालक दल मिशन, संभावित रूप से नवंबर 2024 में लॉन्च होगा।

🔵 वाइपर (नासा):
- भविष्य में मानव चंद्र अन्वेषण के लिए आवश्यक वाष्पशील पदार्थों की खोज के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर मिशन।
- आगे के परीक्षण में देरी के बाद नवंबर 2024 में लॉन्च निर्धारित किया गया।

🌌 लूनर ट्रेलब्लेज़र और प्राइम-1 मिशन (नासा):
- कम लागत वाले ग्रहीय मिशनों के लिए नासा के SIMPLEx कार्यक्रम का हिस्सा।
- लूनर ट्रेलब्लेज़र चंद्रमा की परिक्रमा करता है, पानी के अणुओं के स्थानों का मानचित्रण करता है, जबकि PRIME-1 सतह में ड्रिल करता है।
- प्राथमिक पेलोड की तैयारी के आधार पर संभावित लॉन्च तिथियां 2024 के मध्य तक हो सकती हैं।

🚀 JAXA का मार्टियन मून एक्सप्लोरेशन (MMX) मिशन:
- जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह के चंद्रमाओं, फोबोस और डेमोस का अध्ययन करने का मिशन, जिसका उद्देश्य उनकी उत्पत्ति का निर्धारण करना है।
- पृथ्वी पर लौटने से पहले मंगल ग्रह के चारों ओर तीन साल बिताने के लिए सितंबर 2024 के आसपास लॉन्च की योजना बनाई गई।

🌠 ईएसए का हेरा मिशन:
- नासा के DART मिशन के डिमोर्फोस से टकराने के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन डिडिमोस-डिमोर्फोस क्षुद्रग्रह प्रणाली का अध्ययन करना है।
- हेरा का लक्ष्य क्षुद्रग्रहों के भौतिक गुणों का आकलन करना है और इसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च करने की तैयारी है

सर्वेक्षण के अनुसार, 55% रोगियों को केवल निवारक उपाय के रूप में एंटीबायोटिक्स दी गईं

💊 एंटीबायोटिक उपयोग पैटर्न:
- उपचारात्मक से अधिक निवारक: 50% से अधिक रोगियों को निदान किए गए संक्रमणों का इलाज करने के बजाय निवारक रूप से एंटीबायोटिक्स प्राप्त हुए।
- सीमित निदान पुष्टि: 94% ने पुष्टि निदान से पहले एंटीबायोटिक्स प्राप्त कीं, जो मुख्य रूप से नैदानिक मूल्यांकन पर निर्भर थे।

📊 सर्वेक्षण निष्कर्ष:
- प्रिस्क्रिप्शन सांख्यिकी: पात्र रोगियों में, 72% को एंटीबायोटिक्स निर्धारित की गईं, केवल 45% को चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए।
- अनुभवजन्य थेरेपी: 94% ने पुष्टि किए गए जीवाणु कारणों के बजाय नैदानिक निर्णय के आधार पर एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए, जो अनुभवजन्य थेरेपी की व्यापकता को उजागर करता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध चिंताएँ:
- डब्ल्यूएचओ की मान्यता: विश्व स्वास्थ्य संगठन रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) को एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में पहचानता है।
- प्रतिरोध के कारण: अत्यधिक और अनुचित एंटीबायोटिक उपयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास को प्रेरित करता है।

🌐 WHO कार्यप्रणाली कार्यान्वयन:
- ग्लोबल पॉइंट प्रिवलेंस सर्वे: WHO ने अस्पताल में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने के पैटर्न को समझने के लिए इस पद्धति की शुरुआत की।
- भारत में सीमित उपयोग: भारत में कुछ अध्ययनों ने एंटीबायोटिक उपयोग का आकलन करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया है।

🏥 अस्पताल भिन्नताएँ:
- व्यापक असमानताएँ: अस्पतालों के बीच महत्वपूर्ण अंतर देखा गया, 37% से 100% रोगियों को एंटीबायोटिक्स लिखने से लेकर।
- प्रिस्क्रिप्शन रूट: 86.5% प्रिस्क्रिप्शन गैर-मौखिक तरीकों से थे, जिनमें इंजेक्शन या इन्फ्यूजन का सुझाव दिया गया था।

🔬 एंटीबायोटिक वर्गीकरण और उपयोग:
- AWaRe वर्गीकरण: केवल 38% नुस्खे सर्वोत्तम चिकित्सीय मूल्य (एक्सेस समूह) की पेशकश करने वाले एंटीबायोटिक दवाओं के लिए थे, जबकि 57% वॉच समूह से संबंधित थे, जिनमें प्रतिरोध की संभावना अधिक थी।
- उपयोग के संबंध में: वॉच ग्रुप एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक उपयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोध की उनकी क्षमता के कारण चिंता पैदा करता है।

🇮🇳 एनसीडीसी की भूमिका और पहल:
- एएमआर रोकथाम: एनसीडीसी एंटीबायोटिक उपयोग की निगरानी पर जोर देते हुए रोगाणुरोधी प्रतिरोध रोकथाम पर भारत के कार्यक्रम का नेतृत्व करता है।
- राष्ट्रीय एंटीबायोटिक उपभोग नेटवर्क (एनएसी-नेट): एंटीबायोटिक खपत डेटा संकलित करने और स्वास्थ्य सुविधाओं में उपयोग के रुझान की निगरानी करने के लिए स्थापित किया गया।

स्पेसएक्स का फाल्कन9 भारत का GSAT20 लॉन्च करेगा; ब्रॉडबैंड कवरेज फैलाने के लिए उपग्रह

🚀 स्पेसएक्स के साथ साझेदारी:
- एनएसआईएल ने 2024 की दूसरी तिमाही में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर भारत की ब्रॉडबैंड संचार जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से जीएसएटी -20 लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो स्पेसएक्स के साथ भारत का पहला सहयोग है।

🛰️ GSAT-20 विशिष्टताएँ:
- हाई-थ्रूपुट केए-बैंड उपग्रह को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डिजिटल ऑडियो-वीडियो ट्रांसमिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- वजन 4,700 किलोग्राम है और 32 बीम के साथ 48 जीबीपीएस एचटीएस क्षमता प्रदान करता है, जो अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों को कवर करता है।

📡 सेवा प्रदाताओं की भागीदारी:
- भारतीय सेवा प्रदाताओं ने GSAT-20 पर अधिकांश HTS क्षमता सुरक्षित कर ली है।

🚀 फाल्कन 9 रॉकेट:
- स्पेसएक्स का पुन: प्रयोज्य दो चरण वाला रॉकेट लॉन्च की सुविधा प्रदान करेगा, अंतरिक्ष पहुंच की लागत को कम करेगा और इसे पृथ्वी की कक्षा में पेलोड के लिए परिवहन का एक कुशल माध्यम बना देगा।

📡 मांग-संचालित उपग्रह मिशन:
- एनएसआईएल सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "मांग प्रेरित उपग्रह मिशन" चलाती है, जीसैट-20 का लक्ष्य ब्रॉडबैंड, आईएफएमसी और सेलुलर बैकहॉल सेवाओं के लिए लागत प्रभावी एचटीएस क्षमता प्रदान करना है।

पीएम ने लक्षद्वीप में इंटरनेट केबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया

🏝️ लक्षद्वीप विकास परियोजनाएं:
- कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन, जो पहली बार द्वीपसमूह को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

💰 परियोजना लागत और पहल:
- युवाओं के प्रवासन को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और शैक्षणिक संस्थानों सहित ₹1,156 करोड़ की परियोजनाएं।

🌊 आर्थिक और शैक्षिक पहल:
- समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि और समुद्री शैवाल खेती की संभावनाओं की खोज के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर।